भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3851

दिनांक 11 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

जेंडर बजट आवंटन

3851. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) के जेंडर बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है, तथा वे प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम कौन से हैं जिनके अंतर्गत उक्त निधि का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, विशेष रूप से डेयरी, पशुपालन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं के लिए जेंडर बजट आवंटन का प्रभावी उपयोग और लक्षित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में जेंडर बजटिंग के विकासात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए ऋण उपलब्धता, प्रशिक्षण, सहकारी समितियों, मूल्य संवर्धन और बाजार संबद्धता सहित महिला-केंद्रित सहायता पहलों को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के लिए वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए जेंडर आधारित बजट आवंटन का विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	बजट अनुमान 2024–25	बजट अनुमान 2025–26	बजट अनुमान 2026-27
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)	--	240.00	
डेयरी विकास	--	300.00	
विकास कार्यक्रम - NLM	--		242.40

(ख) और (ग): पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) विभिन्न योजनाएं, अर्थात् राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF), पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (LC&ISS), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं जेंडर-विशिष्ट नहीं हैं और संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं, ये योजनाएं राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को डेयरी, पशुपालन और संबद्ध कार्यकलापों में लगी महिला किसानों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

इन क्षेत्रों में लगी महिलाएं पशुधन उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, दूध उत्पादकता को बढ़ाने, नस्ल सुधार को बढ़ावा देने, बोवाइन प्रजनन सेवाओं को द्वार तक पहुंचाने और बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही विभाग की पहलों से लाभान्वित होती हैं। इसके अलावा, विभाग प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRI) के रूप में महिलाओं की भागीदारी शामिल है, जिससे पशुधन क्षेत्र में उनकी भूमिका सुदृढ़ होगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

******